एशियन चैंपियनशिप जीत कर दीपिका ने भारत को दिलाया ओलंपिक का कोटा
>>14

राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 171

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 29 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

पृष्ठ 16

रिलायंस बनी 10 लाख करोड़ वाली देश की पहली कंपनी

इस वर्ष का प्रदर्शन दमदार, किया आठ, नौ और 10 लाख करोड़ रुपये को पार

नई दिल्ली, प्रेट्र : एशिया के सबसे बड़े धनकुबेर मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) भारतीय इतिहास में 10 लाख करोड़ रुपये मूल्य का आंकड़ा छूने वाली पहली कंपनी बन गई है। शेयर बाजारों में पिछले दो कारोबारी सत्रों में कंपनी का प्रदर्शन दमदार रहा। इसके चलते गुरुवार को कारोबार के आखिर में बीएसई में रिलायंस का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 10,01,555.42 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा।

बीएसई में आरआइएल के शेयर गुरुवार को इंट्रा-डे में 0.90 प्रतिशत उछलकर 1,584 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। इस सप्ताह की शुरुआत से ही कंपनी के शेयर 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने को तैयार थी। कंपनी के शेयरों का इस वर्ष का प्रदर्शन इतना दमदार रहा है कि बीएसई ने जहां इस वर्ष अब तक लगभग 14 प्रतिशत का रिटर्न दिया है, वहीं आरआइएल के शेयरों ने अपने निवेशकों को इससे करीब तीन गुना रिटर्न दिया है। पिछले महीने ही आरआइएल ने नौ लाख करोड़ रुपये बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार किया था। नौ लाख करोड़ रुपये से 10 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में रिलायंस ने महज 27 कारोबारी सत्र लिए। गौरतलब है कि कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर, 2019) के लिए 11,262 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था।

रिलायंस ने ऐसे छुआ आसमान (पूंजीकरण करोड़ रु. में)

दिनांक	शेयर मूल्य	बाजार पूंजीकरण	कितने दिन लगे
02 अगस्त 2005	93.57	103321	–
16 अप्रैल 2007	364.44	203138	424
19 सितंबर 2007	543	302935	110
29 अक्टूबर 2007	707	411078	28
21 जुलाई 2017	793	515400	2410
01 नवंबर 2017	953	603207	70
19 जुलाई 2018	1105	700089	180
23 अगस्त 2018	1270	804533	24
24 अक्टूबर 2019	1437	910587	285
28 नवंबर 2019	1580	1000000	25

बड़ी भारतीय कंपनियों का बाजार मूल्य

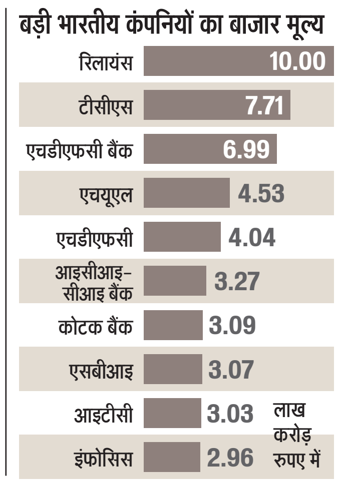

दुनिया की बड़ी पेट्रो कंपनियों का मूल्य

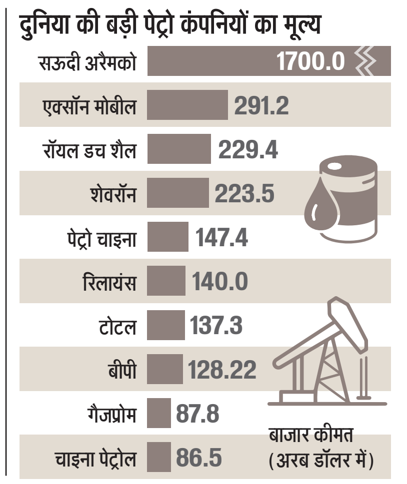

उद्धव राज में माफ होंगे किसानों के कर्ज

ताजपोशी ▶ महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में संभाली कमान, सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा

शिवसेना–राकांपा–कांग्रेस से दो–दो मंत्रियों ने ली शपथ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं पहुंचे

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

अपने संकल्प को पूरा करते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आखिरकार गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। वह महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के दो-दो मंत्रियों ने भी शपथ ली। खास बात यह रही कि न्योते के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समारोह में नहीं पहुंचे। शपथ ग्रहण से दो घंटे पहले तीनों पार्टियों ने सरकार का न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया। इसमें किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी, नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद प्राथमिकता और सेक्युलर मूल्यों पर दृढ़ रहने का वादा किया गया है।

1995 का इतिहास दोहराते हुए दादर स्थित शिवाजी पार्क में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे (59) को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुहूर्त के अनुसार उद्धव ने शाम 6.42 बजे शपथ ग्रहण की। शपथ लेने से पहले उद्धव ने जहां मंच पर रखी छत्रपति शिवाजी महाराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा को प्रणाम किया, वहीं शपथ लेने के बाद जमीन पर मत्था टेकते हुए जनता-जनार्दन को भी प्रणाम किया। इस शपथ ग्रहण समारोह का मंच उनके पिता शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे के स्मृतिस्थल से चंद कदमों की दूरी पर बनाया गया था। 2013 में बालासाहब ठाकरे के निधन के बाद इसी शिवाजी पार्क में उनकी अंत्येष्टि की गई थी। इसी शिवाजी पार्क में बालासाहब हर साल दशहरे के दिन शिवसैनिकों की विशाल सभा को संबोधित करते आए थे। यही नहीं, 1995 में पहली बार बनी शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने भी इसी शिवाजी पार्क में शपथ ली थी। तब मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के मनोहर जोशी और उपमुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के गोपीनाथ मुंडे को शपथ दिलाई गई थी।

जयंत पाटिल हो सकते हैं उपमुख्यमंत्री : माना जा रहा है कि जयंत पाटिल नई सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की भूमिका निभाएंगे। लेकिन राकांपा से बगावत कर फड़नवीस के साथ उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार की सरकार में भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है।

ये नेता रहे मौजूद : शपथ ग्रहण समारोह में इस गठबंधन सरकार के शिल्पकार शरद पवार के अलावा पूर्व सीएम देवेंद्र फड़नवीस, उद्योगपति मुकेश अंबानी और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी उपस्थित थे। कभी शिवसेना में बालासाहब के राजनीतिक उत्तराधिकारी माने जाने वाले उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे भी थे तो तमिलनाडु के राजनीतिक दल द्रमुक के नेता स्टालिन और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी नजर आ रहे थे।

उद्धव की राह में बिछाए दो टन फूल पेज>>4

मुंबई में गुरुवार को शिवाजी पार्क में आयोजित समारोह में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उपस्थित जनसमूह का कुछ इस तरह अभिवादन किया। एएनआइ

> महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर उद्धव ठाकरे जी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वह महाराष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी लगन से काम करेंगे।
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इन मंत्रियों ने ली शपथ

- एकनाथ शिंदे (शिवसेना)
- सुभाष देसाई (शिवसेना)
- जयंत पाटिल (राकांपा)
- छगन भुजबल (राकांपा)
- बालासाहब थोरात (कांग्रेस)
- नितिन राउत (कांग्रेस)

पहली कैबिनेट बैठक में रायगढ़ किले के लिए 20 करोड़ मंजूर

मुंबई, प्रेट्र : शपथ ग्रहण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक के बाद उद्धव ने बताया, कैबिनेट ने पहला फैसला रायगढ़ किले के संरक्षण के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर करने का लिया है। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करती थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'हमें वास्तविकता पता हो तो हम बेहतर योजना बना सकते हैं। इसके लिए हमने मुख्य सचिव से जानकारियां मांगी हैं। किसानों को अब तक आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। हम किसानों को ठोस मदद मुहैया कराना चाहते हैं ताकि उनके हालात में सुधार हो सके। हम राज्य में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां कोई भी आतंकित महसूस न करे।'

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

- नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80 फीसद आरक्षण
- सरकारी पदों पर तुरंत भर्ती
- किसान बीमा योजना में सुधार
- 10 रुपये में भोजन की थाली योजना
- तालुका स्तर पर एक रुपया क्लीनिक
- गरीब कन्याओं को मुफ्त शिक्षा
- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल
- दो समन्वय समितियां बनेंगी

रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से प्रज्ञा ठाकुर बाहर

- भाजपा ने संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर रोक लगाई
- लोकसभा में राजनाथ बोले, गोडसे को देशभक्त बताने वाली सोच निंदनीय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा में दिए विवादित बयान को लेकर भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर चौतरफा घिर गई हैं। खुद उनकी पार्टी भाजपा ने संसदीय दल की बैठक में भाग लेने पर रोक लगाने के साथ ही रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से बाहर कर दिया है। वहीं दूसरी ओर संप्रग के विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बैकफुट पर आई भाजपा ने खुद को प्रज्ञा ठाकुर के बयान से अलग कर लिया है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संसदीय इतिहास का दुखद दिन बताते हुए भाजपा-आरएसएस की सोच करार दिया है।

प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी संसदीय दल की बैठक में उनके भाग लेने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर का बयान निंदनीय है और भाजपा ऐसे बयान और विचार का कभी समर्थन नहीं करती है। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है और वे खुद ऐसी विचारधारा की निंदा करते हैं। लेकिन, असंतुष्ट विपक्षी सांसदों ने सदन का बहिष्कार किया। अपने विवादित बयानों को लेकर पार्टी की किरकिरी कराने वाली प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पार्टी इस बार कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस बीच प्रज्ञा ने सफाई देकर अपना बचाव करने की कोशिश की। उनका कहना था कि उन्होंने ऊधम सिंह को देशभक्त बताया था, नाथूराम गोडसे को नहीं।

वहीं, भाजपा की कार्रवाई और प्रज्ञा ठाकुर की सफाई से असंतुष्ट विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है। संप्रग के सांसदों ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि पूरे सदन को इस बयान के लिए प्रज्ञा ठाकुर की निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आतंकी प्रज्ञा ने आतंकी गोडसे को देशभक्त बताया। यह भारत के संसदीय इतिहास का एक दुखद दिन है। बाद में संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जो भी कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के दिल की बात है। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से निकालने की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए देश भाजपा को माफ नहीं करेगा।

प्रज्ञा ठाकुर। फाइल फोटो

साध्वी प्रज्ञा हैं कि मानती ही नहीं

भोपाल : यह पहला मौका नहीं है, जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कारण भाजपा को जवाब देना मुश्किल हुआ हो। विवादों से उनका गहरा और पुराना नाता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के समय अपने विवादास्पद बयानों से साध्वी ने पार्टी को मध्य प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी परेशानी में डाल दिया था। (पेज–6)

सरोकार

कोयले से लिखना सीखा, मिटा रहीं अशिक्षा की कालिख

जौनपुर : चूल्हे से निकले कोयले से लिखना सीखकर पढ़ाई शुरू करने वाली मुन्नी बेगम जीवट के बूते परास्नातक तक पहुंचीं। अब तक पांच हजार महिलाओं को भी साक्षर कर चुकीं मुन्नी को उपराष्ट्रपति के हाथों एक्जांपल अवार्ड मिल चुका है। (पेज–10)

जागरण विशेष

गैस चूल्हे पर खाना पकाने के साथ मोबाइल भी करें चार्ज

लखनऊ : बर्नर की आंच को बर्बाद नहीं होने देगा यह 'एनर्जी अर्नर' डिवाइस। लखनऊ के होनहार छात्र द्वारा तैयार किए गए मॉडल ने एशियन इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम में जीता पहला पुरस्कार। (पेज–10)

न्यूज गैलरी

राज–नीति ▶ पृष्ठ 3

पीएमओ ने दिया रेल किराये में बढ़ोतरी का सुझाव

नई दिल्ली : रेलवे की नाजुक माली हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रेल मंत्रालय से यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाने को कहा है। पीएमओ का कहना है कि स्थिति को देखते हुए रेलवे को एक–दो महीने में किराया बढ़ाना चाहिए और उससे पहले लोगों को इसका औचित्य बताना चाहिए। पीएमओ ने रेलवे को आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नए उपाय अपनाने को भी कहा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

सीबीआइ ने अब सेंगर को बताया हत्या का आरोपित

नई दिल्ली : उन्नाव कांड की जांच कर रही सीबीआइ ने पीड़िता के पिता की मौत के मामले में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ अब हत्या का आरोप-पत्र दायर किया है, जबकि तीस हजारी अदालत पहले ही सेंगर के खिलाफ हत्या का आरोप तय कर चुकी है। सीबीआइ ने पूर्व में दायर आरोप-पत्र में सेंगर को हत्या का आरोपित नहीं माना था।

विश्वास.News

मधुमक्खी के जहर से संक्रमण ठीक होने का दावा फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल • पेज 10

वाट्सएप ने नहीं दी जासूसी पीड़ितों की जानकारी

- सरकार ने राज्यसभा में कहा, कंपनी ने अपनी कमजोर कड़ियां भी नहीं बताईं
- कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर के जवाब पर असंतोष जताया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वाट्सएप के सीईओ के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने अपने सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों जानकारी नहीं दी थी। इतना ही नहीं अभी तक वाट्सएप कंपनी पेगासस सॉफ्टवेयर का शिकार हुए लोगों के नामों तक की जानकारी नहीं दे पाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार ने इस मामले में अनधिकृत तरीके से कोई दखलंदाजी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल कंपनियों को कड़ी सुरक्षा रखनी होगी अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

गुरुवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रसाद ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने इजरायली टेक्नोलॉजी कंपनी एनएसओ समूह को भी 26 नवंबर को एक नोटिस भेजा जिसमें मालवेयर के बारे में जानकारी और भारतीय उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव का विवरण मांगा गया था। उन्होंने कहा कि डिजिटल कंपनियों को यह स्वीकार करने और समझने की आवश्यकता है कि भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा वास्तव में महत्वपूर्ण है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने चाहिए। इसमें विफल होने पर सरकार आइटी कानून के तहत उचित कार्रवाई भी कर सकती है।

प्रसाद ने कहा कि 5 सितंबर को वाट्सएप ने सर्ट इन (कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम) को मई में रिपोर्ट की गई सुरक्षा घटना के बारे में अपडेट प्रदान करते हुए लिखा और कहा कि यद्यपि इस हमले की पूरी सीमा कभी भी ज्ञात नहीं हो सकती, फिर भी वाट्सएप उपलब्ध सूचनाओं की लगातार समीक्षा करता रहा है। उपलब्ध लॉग डाटा के आधार पर वाट्सएप का मानना है कि हो सकता है हमलावरों ने भारत में लगभग 121 उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास किया हो। प्रसाद ने इस संबंध में सदन में रखे अपने विवरण पत्र में कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाट्सएप ने खेद व्यक्त किया है कि वे उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसियां तय मानकों के अनुरूप ही इस मामले की जांच कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के इस जवाब पर दिग्विजय सिंह ने असंतोष जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें यह स्पष्ट जवाब देना होगा कि सरकार या किसी एजेंसी ने पेगासस खरीदा है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाट्सएप के मालिक फेसबुक के कुछ वरिष्ठ अफसरों से मुलाकात की थी और पेगासस को लेकर चर्चा की थी।

ट्रंप के हांगकांग बिल पर दस्तखत से चीन लाल

- राजदूत को तलब कर दी दुष्परिणामों की चेतावनी, कहा, हांगकांग के मामलों में अमेरिका दे रहा दखल

बीजिंग, रायटर : हांगकांग पर संसद के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत से चीन भड़क उठा है। कानून में तब्दील इस दस्तावेज के मुताबिक हांगकांग को अमेरिका से मिले खास कारोबारी दर्जे की हर साल समीक्षा होगी, इसके बाद अगले साल के लिए उसे जारी रखा जाएगा। यह समीक्षा मानवाधिकारों के पालन को मानदंड बनाकर होगी। साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन के चीन और हांगकांग के अधिकारियों को अमेरिका प्रतिबंधित करेगा। चीन ने कहा है कि इस कानून के लागू होने से दोनों देशों रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा और इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे।

ट्रंप ने चंद रोज पहले हांगकांग मसले पर संसद के पारित प्रस्ताव पर दस्तखत न करने के संकेत देने के बावजूद बुधवार को अचानक यह बड़ा कदम उठाया। ट्रंप ने संबंध बिगड़ने की चीन की पूर्व चेतावनी के बावजूद संसद के प्रस्ताव पर दस्तखत किए। अमेरिका ने यह कानून तब बनाया है जब उसकी चीन के साथ कारोबार में समझौते के लिए वार्ता महत्वपूर्ण दौर में है। हांगकांग का लोकतंत्र की मांग वाला छह महीने पुराना आंदोलन भी ठंडा पड़ने लगा है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से आंदोलन में फिर गर्माहट पैदा होने के आसार हैं।

चीन ने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से हांगकांग में मनमानी को बढ़ावा मिलेगा। अब इसको रोकने के लिए चीन जो कदम उठाएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। चीन के उप विदेश मंत्री ली यूचेंग ने गुरुवार को अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रांसटेड को तलब कर ट्रंप के कदम पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिका को चीन के घरेलू मामलों में दखलंदाजी से बाज आने की चेतावनी दी। कहा, इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो सकते हैं। जबकि हांगकांग की चीन समर्थित सरकार ने कहा है कि अमेरिकी कानून का आंदोलनकारियों के बीच गलत संदेश गया है। अमेरिका के समर्थन में लिए गए बड़े कदम के बावजूद गुरुवार को हांगकांग में शांति बनी रही। कोई बड़ा आंदोलन न होने की खबर है। इस बीच 100 पुलिसकर्मियों ने सादे कपड़ों में पॉलीटेक्निक विश्वविद्यालय के भीतर जाकर वहां हिंसक आंदोलनकारियों के खिलाफ सुबूत एकत्रित किए। ये अपने साथ कई हस्तनिर्मित हथियार लेकर आए हैं जिनमें पेट्रोल बम और तीर-धनुष शामिल हैं।

डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)। रायटर

कारगर कदम

जम्मू–कश्मीर में अगस्त से अक्टूबर तक सिर्फ 16 युवाओं ने पकड़ी आतंक की राह, सुरक्षा बलों की मुहिम से भी टूट रहा है आतंकी संगठनों का मनोबल

इंटरनेट पर पाबंदी से जिहादी दुष्प्रचार पर शिकंजा

नवीन नवाज, जम्मू

जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी का असर जिहादी दुष्प्रचार पर भी साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि राज्य के पुनर्गठन के फैसले के बाद से आतंक के दलदल में फंसने वाले युवाओं की संख्या में काफी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त से अक्टूबर तक मात्र 16 युवाओं ने आतंकियों और ओवर ग्राउंड वर्करों (ओडब्ल्यूजी) के दुष्प्रचार में फंसकर हथियार उठाए हैं। सुरक्षा बलों की मुहिम का असर भी आतंकी संगठनों के मनोबल को तोड़ रहा है। वहीं, इस साल करीब 110 युवा अमन के पथ से भटककर आतंकी बने हैं। यह संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले करीब आधी है।

जानकारी के अनुसार, एक जनवरी 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक जम्मू-कश्मीर में 447 स्थानीय लड़के आतंकी बने हैं। सबसे ज्यादा 209 युवकों ने पिछले साल आतंक की राह पकड़ी। इस दौरान यह बात सामने आई थी कि अधिकतर युवा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठनों के दुष्प्रचार का शिकार हुए थे। पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का प्रस्ताव लाने से पूर्व पूरे जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। वादी में फोन सेवा भी बंद थी। हालांकि अब मोबाइल सेवा करीब एक माह पहले बहाल की जा चुकी है, लेकिन इंटरनेट सेवा अब भी चुनिंदा सरकारी कार्यालयों में ही कड़ी निगरानी के बीच उपलब्ध है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक का असर कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। हिंसक प्रदर्शनों में लगातार कमी आ रही है।

सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा था जहर : जम्मू-कश्मीर में आतंकरोधी अभियानों से जुड़े एसएसपी इम्तियाज हुसैन मीर के अनुसार बीते छह वर्षों में सोशल मीडिया के दुष्प्रचार ने सबसे अधिक युवाओं के दिमाग में जहर भरा है। इसके अलावा सक्रिय ओजीडब्ल्यू भी युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदी से इस दुष्प्रचार पर रोक लगी है। साथ ही राज्य के पुनर्गठन के साथ आतंकियों का एजेंडा भी समाप्त हो गया है।

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के मुताबिक इस अगस्त से अक्टूबर तक सिर्फ 16 लड़के ही आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। अगस्त में सिर्फ दो लड़कों के आतंकी बनने की पुष्टि हुई थी। अलबता, वर्ष 2018 के अगस्त माह में 17, सितंबर में 13 और अक्टूबर माह में 14 युवाओं ने आतंक का रास्ता पकड़ा था। इस वर्ष हिजबुल मुजाहिदीन से 46, जैश से 34 और लश्कर से 22 युवा जुड़े हैं। दक्षिण कश्मीर अब भी आतंक की नर्सरी बना हुआ है और इस वर्ष कुल 110 में से सबसे ज्यादा 36 युवक पुलवामा से आतंकी बने हैं। बीते साल भी पुलवामा से ही सबसे ज्यादा 94 युवा आतंकवाद की राह पर फिसल गए थे।

कश्मीर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंक की राह पकड़ने वाले युवाओं की घर वापसी के लिए सुरक्षा बलों ने विशेष अभियान छेड़ रखा हैं। सेना का ऑपरेशन मां काफी चर्चा में है। ऐसे करीब 70 युवाओं को बचाने में सफलता मिली है।

प्रतीकात्मक

अब कश्मीरी नेताओं को विदेश जाने की अनुमति

जम्मू : जम्मू–कश्मीर में बने राजनीतिक शून्य को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। पांच अगस्त को एहतियातन हिरासत में लिए गए कई नेताओं को जहां क्रमानुसार रिहा किया जा रहा है। वहीं, कई नेताओं को विदेश जाने की अनुमति दी है ताकि वह संबंधित पक्षों से जुड़े लोगों से संपर्क कर राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली का रास्ता खोल सकें। घरों में नजरबंद किए गए नेताओं को आपात परिस्थितियों में जम्मू या दिल्ली जाने की छूट भी दी गई है। हालांकि वादी में उन्हें नजरबंद रखा जाएगा। (पेज–6)

झारखंड के मतदान दल के 18 लोगों को छत्तीसगढ़ में छोड़ गया हेलीकॉप्टर

नईदुनिया, अंबिकापुर

झारखंड के नक्सल प्रभावित लातेहार जिले के आठ पोलिंग बूथों पर तैनात मतदान दल के 18 अधिकारियों-कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर भैंसामुंडा स्थित सत्तीपारा के खुले मैदान में उतार कर वापस चला गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर घंटों बाद पोलिंग पार्टियों को वापस ले जाने हेलीकॉप्टर आया।

जानकारी के अनुसार झारखंड में 30 नवंबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए आठ पोलिंग पार्टियों को दोपहर करीब 12 बजे लातेहार से सेना के हेलीकॉप्टर से मनिका विधानसभा क्षेत्र के चटकपुर इलाके में स्थित अलग-अलग मतदान केंद्रों के लिए भेजा गया था। लेकिन, हेलीकॉप्टर भटक कर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला स्थित प्रतापपुर भैंसामुंडा से लगे सत्तीपारा के खुले मैदान में उतरा। पायलट को लगा कि इसी स्थान पर उन्हें उतारना है। हेलीकॉप्टर उतरता देख मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पोलिंग पार्टियों को जब पता चला कि वे झारखंड के अपने पोलिंग सेंटर को छोड़ छत्तीसगढ़ इलाके में उतर गए हैं तो अफरातफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी जानकारी सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी को दी। कलेक्टर ने तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी। इसकी जानकारी झारखंड राज्य के निर्वाचन आयोग तक भेजी गई। दोपहर करीब दो बजे हेलीकॉप्टर लातेहार (झारखंड) से वापस आया और मतदान दल को लेकर वापस लौटा।

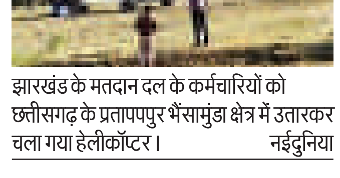

झारखंड के मतदान दल के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ के प्रतापपपुर भैंसामुंडा क्षेत्र में उतारकर चला गया हेलीकॉप्टर। नईदुनिया